गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 069
दि. 08.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

जुलाई की जोरदार बारिश से संभला मानसून, लेकिन खतरा बरकरार : जून की बड़ी कमी घटी, फिर भी देश के कई हिस्से अब भी सूखे; कहीं बाढ़ तो कहीं बारिश का इंतजार

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने जुलाई की शुरुआत के साथ देशभर में रफ्तार पकड़ ली है और पहले सप्ताह में हुई तेज बारिश ने जून महीने के दौरान बनी वर्षा की बड़ी कमी को काफी हद तक कम कर दिया है। हालांकि राहत के बावजूद तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून का स्वरूप सामान्य वर्षों से अलग दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है, जबकि देश का बड़ा हिस्सा अब भी सामान्य से कम वर्षा का सामना कर रहा है। यही कारण है कि एक ओर बाढ़ और जलभराव जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो दूसरी ओर अनेक इलाकों में किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच देशभर में 65.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। यह केवल छह दिनों में हुई बारिश जून महीने की कुल वर्षा का लगभग 60 प्रतिशत है। वर्ष 1901 से अब तक के रिकॉर्ड देखें तो जुलाई के पहले सप्ताह की यह बारिश 23वीं सबसे अधिक वर्षा वाले शुरुआती सप्ताहों में शामिल है। इससे स्पष्ट है कि जुलाई की शुरुआत मानसून के लिहाज से काफी सक्रिय रही है। जून के अंत तक देश में मानसूनी वर्षा सामान्य से 31.4 प्रतिशत कम दर्ज की गई थी। उस समय यह आशंका जताई जा रही थी कि यदि जुलाई में भी बारिश कमजोर रही तो खरीफ फसलों, जलाशयों और पेयजल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन जुलाई के पहले छह दिनों में लगातार सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण यह कमी तेजी से घटकर सिर्फ 17 प्रतिशत रह गई है। इससे कृषि क्षेत्र और जल संसाधनों को कुछ राहत मिली है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल राष्ट्रीय औसत को देखकर पूरी स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। यदि वर्ष 1901 से अब तक के मानसूनी रिकॉर्ड से तुलना की जाए तो मौजूदा मानसून अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर माना जा रहा है और अब तक की स्थिति के आधार पर यह 22वां सबसे शुष्क मानसून दर्ज हो सकता है।

मौसम विभाग के आंकड़े और ग्रिड आधारित वर्षा विश्लेषण में कुछ तकनीकी अंतर जरूर हैं, लेकिन दोनों ही स्रोत यह संकेत देते हैं कि मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि असमानता अभी भी बनी हुई है। इस वर्ष मानसून की सबसे बड़ी विशेषता इसकी असमान और अत्यधिक तीव्र वर्षा रही है। भारतीय मौसम विभाग वर्षा को उसकी तीव्रता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। 24 घंटे में 7.5 मिलीमीटर तक वर्षा को हल्की, 7.6 से 35.5 मिलीमीटर तक मध्यम, 35.6 से 244.4 मिलीमीटर तक भारी तथा इससे अधिक वर्षा को अत्यधिक भारी वर्षा की श्रेणी में रखा जाता है। जुलाई के पहले सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि सामान्य या हल्की बारिश की तुलना में भारी और अत्यधिक भारी वर्षा की घटनाएं अधिक दर्ज हुई हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार मध्यम से अधिक तीव्रता वाली बारिश सामान्य औसत की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत अधिक रही है, जबकि हल्की बारिश में यह बढ़ोतरी केवल लगभग 7.6 प्रतिशत दर्ज की गई। इसका अर्थ यह है कि बारिश धीरे-धीरे और लंबे समय तक होने के बजाय कम समय में बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। यही वजह है कि कई शहरों में कुछ घंटों की बारिश ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रही है।

मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि वातावरण में बढ़ती नमी और तापमान के कारण अब वर्षा की प्रकृति बदल रही है। पहले जहां कई दिनों तक लगातार मध्यम वर्षा होती थी, वहीं अब कम समय में अत्यधिक पानी बरसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में जलभराव, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

मुंबई, सूरत, पुणे, वायनाड और देश के कई अन्य शहरों में हाल के दिनों में देखे गए हालात इसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। अधिकांश महानगरों की जल निकासी व्यवस्था कई दशक पहले तैयार की गई थी और उसे सामान्य वर्षा को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। लेकिन अब जब कुछ घंटों में ही कई दिनों के बराबर बारिश हो जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह जवाब दे देता है। परिणामस्वरूप सड़कें नदी में बदल जाती हैं, यातायात ठप हो जाता है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है।

हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा की कमी कम हुई है, लेकिन इसका लाभ पूरे देश को समान रूप से नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 46 प्रतिशत क्षेत्र में अभी भी सामान्य से 20 प्रतिशत या उससे अधिक वर्षा की कमी बनी हुई है। इसके विपरीत लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्रों में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में हुई अत्यधिक बारिश राष्ट्रीय औसत को बेहतर बना रही है, जबकि बड़ी आबादी वाले कई इलाके अब भी पर्याप्त वर्षा से वंचित हैं।

जिन क्षेत्रों में इस बार सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है उनमें मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों में कई स्थानों पर नदियां उफान पर हैं, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम और कुछ मध्य भारतीय क्षेत्रों में अभी भी सामान्य वर्षा का इंतजार बना हुआ है।

फिर भी जुलाई की सक्रिय शुरुआत का एक सकारात्मक प्रभाव यह रहा है कि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों का दायरा बढ़ा है। जून के अंत तक देश के केवल 19.6 प्रतिशत भूभाग में सामान्य वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि 6 जुलाई तक यह बढ़कर 30.8 प्रतिशत हो गई। इससे संकेत मिलता है कि मानसून धीरे-धीरे अधिक क्षेत्रों में सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यदि बारिश का यह क्रम जारी रहा तो वर्षा का वितरण और संतुलित हो सकता है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई का महीना खरीफ फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, दालें और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई तथा शुरुआती वृद्धि इसी अवधि की वर्षा पर निर्भर करती है। इसलिए जुलाई में अच्छी बारिश होने से किसानों को राहत मिल सकती है, बशर्ते वर्षा का वितरण संतुलित रहे और अत्यधिक बारिश से फसलें प्रभावित न हों।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब चुनौती केवल अधिक बारिश की नहीं, बल्कि उसके समान वितरण की है। यदि मानसून का वर्तमान पैटर्न जारी रहता है तो एक ओर कुछ राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना रहेगा, जबकि दूसरी ओर वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि और जल संकट की चिंता भी बनी रह सकती है। ऐसे में प्रभावी जल प्रबंधन, शहरी जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर समय रहते तैयारी करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

पर्यावरण मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ से तीन अधिकारी हटाए गए, फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय से तीन वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ हटा दिया गया है। इनमें मंत्री के निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) और दो अतिरिक्त निजी सचिव (एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी) शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, यह कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई है। हालांकि आदेशों में इन बदलावों के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है, वहीं विपक्ष ने भी इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 3 जुलाई को जारी तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से इन अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त किए जाने की जानकारी दी गई। आदेशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त कर उनके मूल विभाग, राजस्व विभाग, में वापस भेज दिया गया है। अमर सिंह वर्ष 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं और मंत्री कार्यालय में निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। मंत्रालय ने उनके स्थानांतरण का कारण केवल

"प्रशासनिक आधार" बताया है।

इसी क्रम में मंत्री कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्यरत आयुष सरन की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनका कार्यकाल समाप्त किया जा रहा है, हालांकि इसके पीछे कोई विस्तृत कारण नहीं बताया गया।

तीसरे अधिकारी शैलेश कुमार सिंह, जो केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं और मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्हें भी समय से पहले उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में "विस्तारित कूलिंग अवधि" के प्रावधान के साथ वापस भेजा गया है। यह निर्णय भी तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

मंत्रालय द्वारा जारी इन तीनों आदेशों की प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी गई हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यह एक नियमित प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन एक साथ तीन वरिष्ठ अधिकारियों के हटाए जाने से इस निर्णय को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

हालांकि मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है और आदेशों में किसी प्रकार की अनियमितता, जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों में केवल अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से मुक्त कर मूल विभाग या कैडर में भेजे जाने की जानकारी दी गई है।

इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक साथ मंत्री कार्यालय के कई अधिकारियों का हटाया जाना असामान्य प्रतीत होता है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के घटनाक्रम कई सवाल खड़े करते हैं और सरकार को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की और इसे लेकर राजनीतिक सवाल उठाए।

हालांकि केंद्र सरकार या पर्यावरण मंत्रालय की ओर से विपक्ष की टिप्पणियों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मंत्रालय ने अपने आदेशों में केवल प्रशासनिक बदलाव की जानकारी दी है और इससे आगे कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न मंत्रालयों में समय-समय पर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और मूल कैडर में वापसी जैसी प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। हालांकि किसी मंत्री के कार्यालय से एक साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों का हटाया जाना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है, विशेषकर तब जब आदेशों में विस्तृत कारणों का उल्लेख न किया गया हो।

फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय में इन पदों पर नई नियुक्तियों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आने वाले दिनों में मंत्रालय इन रिक्त पदों को भरने के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। वहीं, इस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी रहने की संभावना है।

जगन्नाथ परंपरा को लेकर नया विवाद : समय से पहले रथ यात्रा निकालने पर इस्कॉन के खिलाफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

भुवनेश्वर। भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा और उससे जुड़ी धार्मिक परंपराओं को लेकर नया विवाद सामने आया है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) के अध्यक्ष तथा गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस्कॉन (इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस) द्वारा भारत और विदेशों में निर्धारित तिथि से पहले आयोजित की जा रही 'स्नान यात्रा' और 'रथ यात्रा' पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रकार के आयोजन सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और शास्त्रीय मर्यादाओं के विपरीत हैं तथा इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो रही हैं।

गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव ने अपने पत्र में कहा कि भगवान जगन्नाथ से जुड़े सभी प्रमुख उत्सवों का आयोजन निर्धारित धार्मिक पंचांग, शास्त्रों और परंपरागत विधि-विधान के अनुसार होना चाहिए। उनका आरोप है कि इस्कॉन लंबे समय से इन परंपराओं से अलग हटकर विभिन्न देशों में निर्धारित समय से पहले 'स्नान यात्रा' और 'रथ यात्रा' आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय

पर कई बार इस्कॉन से अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति पिछले लगभग दो दशकों से इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। इस दौरान ओडिशा सरकार ने भी कई अवसरों पर इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की और पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप आयोजन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बावजूद विदेशों में समय से पहले आयोजित होने वाली इन यात्राओं का सिलसिला जारी है।

चार जुलाई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में दिव्यसिंह देव ने उल्लेख किया कि भगवान जगन्नाथ की परंपरा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली परंपरा की पवित्रता और प्रामाणिकता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक विश्वास सुरक्षित रह सकें।

भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले गजपति महाराजा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाए और संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में भगवान जगन्नाथ से जुड़े सभी प्रमुख धार्मिक उत्सव शास्त्रों और पारंपरिक पंचांग के अनुरूप ही आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि समय से पहले आयोजित की जाने वाली 'स्नान यात्रा' और 'रथ यात्रा' जैसी परंपराएं मूल धार्मिक व्यवस्था से मेल नहीं खातीं और इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति, जो पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर की सर्वोच्च नीतिगत संस्था है, लंबे समय से मंदिर की धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और व्यवस्थाओं के संरक्षण का दायित्व निभा रही है। समिति का कहना है कि मंदिर से जुड़ी प्रत्येक परंपरा सदियों से निश्चित नियमों और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर संचालित होती रही है, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अलग व्यवस्था अपनाना उचित नहीं माना जा सकता।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्वभर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। भारत के अलावा अनेक देशों में भी इस्कॉन द्वारा हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। हालांकि पुरी मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन आयोजनों की तिथियां मूल धार्मिक परंपरा और पंचांग के अनुरूप होनी चाहिए।

फिलहाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए इस पत्र पर केंद्र सरकार या इस्कॉन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में सरकार क्या रुख अपनाती है और परंपराओं तथा वैश्विक स्तर पर आयोजित धार्मिक आयोजनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

रहने योग्य शहरों की वैश्विक रैंकिंग में दिल्ली-मुंबई फिर पिछड़े, टॉप-100 से बाहर; कोपेनहेगन लगातार दूसरे वर्ष बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बेहतर और रहने योग्य शहरों की नई वैश्विक रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा जारी वर्ष 2026 की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली को 120वां और मुंबई को 121वां स्थान मिला है। दोनों भारतीय महानगर लगातार दूसरे वर्ष भी दुनिया के शीर्ष 100 रहने योग्य शहरों में जगह बनाने में असफल रहे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में दोनों शहरों की रैंकिंग में सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन विकसित देशों के शहरों की तुलना में अभी भी बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी नियोजन और जीवन की गुणवत्ता के कई मानकों पर इन्हें लंबा सफर तय करना बाकी है।

ईआईयू की इस वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया के 173 प्रमुख शहरों का मूल्यांकन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, संस्कृति और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया है। इन सभी श्रेणियों में प्राप्त अंकों के आधार पर शहरों की समग्र रैंकिंग तैयार की गई। इस वर्ष भी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने लगातार दूसरे साल दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर का स्थान बरकरार रखा। इससे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीन वर्षों तक पहले स्थान पर रही थी, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी वह शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर सकी।

रिपोर्ट के अनुसार कोपेनहेगन ने स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी तीन प्रमुख श्रेणियों में 100 में से पूरे 100 अंक हासिल किए। शहर की उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सुरक्षित माहौल और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सुविधाओं ने उसे लगातार शीर्ष स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का कहना है कि कोपेनहेगन में सतत विकास, हरित परिवहन, साइकिल संस्कृति और नागरिक सुविधाओं पर लगातार निवेश ने इसे दुनिया के सबसे बेहतर शहरों में बनाए रखा है।

दिल्ली और मुंबई की बात करें तो दोनों शहरों ने अपनी पिछले वर्ष की रैंकिंग बरकरार रखी है। दिल्ली 120वें और मुंबई 121वें स्थान पर रही। दोनों शहरों का समग्र स्कोर विभिन्न श्रेणियों में लगभग 50 से 60 अंकों के बीच रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इन दोनों महानगरों ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में कुछ सुधार अवश्य किए हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, यातायात का दबाव, प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ और शहरी प्रबंधन जैसी चुनौतियां अब भी उनकी रैंकिंग को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और मुंबई की वैश्विक स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2023 में दोनों शहर 141वें स्थान के आसपास थे, जबकि अब वे 120वें और 121वें स्थान तक पहुंच चुके हैं। इससे संकेत मिलता है कि धीरे-धीरे शहरी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शीर्ष शहरों तक पहुंचने के लिए अभी काफी प्रयासों की आवश्यकता है।

ईआईयू वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष यह वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी कर रहा है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी विकास की गुणवत्ता का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट का उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निवेशक, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए करती हैं।

इस वर्ष की रिपोर्ट में एशिया का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। एशियाई शहरों का औसत स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 अंक बढ़कर 73.9 तक पहुंच गया, जिससे एशिया इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा। रिपोर्ट में शामिल 58 एशियाई शहरों में कई शहरों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है।

विशेष रूप से चीन ने इस वर्ष की रैंकिंग में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। रिपोर्ट में शामिल सभी 19 चीनी शहरों के स्वास्थ्य संबंधी स्कोर में सुधार देखने को मिला। ईआईयू के अनुसार चीन सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा के विस्तार, चिकित्सा सुविधाओं में निवेश और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की श्रेणी में चीन के पांच शहरों ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि सबसे अधिक सुधार करने वाले शहरों की सूची में भी चीनी शहरों का दबदबा रहा।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि किसी शहर की रहने योग्य स्थिति केवल आधुनिक इमारतों या आर्थिक विकास से तय नहीं होती, बल्कि नागरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन और सांस्कृतिक जीवन जैसे अनेक कारक मिलकर किसी शहर को रहने योग्य बनाते हैं। जिन शहरों ने इन क्षेत्रों में लगातार निवेश किया है, वे शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं।

दूसरी ओर, सूची के सबसे निचले स्थानों पर वे शहर हैं जो लंबे समय से युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट या गंभीर गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार निचले दस शहरों में अधिकांश ऐसे हैं जहां सुरक्षा की स्थिति बेहद कमजोर है और बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

सीरिया की राजधानी दमिश्क इस वर्ष भी दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिसंबर 2024 के बाद वहां स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कुछ सुधार दर्ज किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्गठित करने के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है, लेकिन वर्षों के गृहयुद्ध के कारण शहर अभी भी सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक स्थिरता जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के महानगरों के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण संकेत है। तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए भविष्य में परिवहन, जल निकासी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्रों के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा पर अधिक निवेश करना आवश्यक होगा। यदि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध और दीर्घकालिक सुधार किए जाते हैं, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली, मुंबई और अन्य भारतीय शहर वैश्विक लिवेबिलिटी रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहरों की सूची में भारत की सबसे बड़ी चुनौती अपने महानगरों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ, टिकाऊ और नागरिक-अनुकूल बनाना है।

संपादकीय

विश्वास बहाली जरूरी

देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था-विश्वास को आहत करने वाला चंदा-चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में आखिरकार महामंत्री चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब ट्रस्ट के अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। राममंदिर के चंदे में हेरफेर से उठे देशव्यापी विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज होने, एसआईटी के गठन और कुछ गिरफ्तारियों के बाद ये इस्तीफे अपरिहार्य थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दो इस्तीफों से श्रद्धालुओं के भरोसे की बहाली हो पाएगी? जैसा कि नवनियुक्त अंतरिम महामंत्री कृष्ण मोहन ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा,उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने स्वीकारा कि ट्रस्ट प्रबंधन और संचालन में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास होगा। साथ ही माना कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे न्यास की छवि धूमिल हुई है। एक अविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को फिर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा में शामिल होने से पहले कुछ सालों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु वैज्ञानिक भी रहे हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं। वे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने सोमवार को अयोध्या में उन बहुमूल्य वस्तुओं को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया, जिनके गायब होने को लेकर अटकलें लगायी जा रही थीं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के संचालन के लिये विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक बाईस जुलाई को होगी। जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि तब तक चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी।

लेकिन सवाल यह है कि आस्था व विश्वास से खिलवाड़ के कृत्य की जांच के लिये क्या एसआईटी की जांच पर्याप्त है? क्या चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मात्र से उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवहार पर कार्रवाई पूरी मान ली जाए? क्या इतनी कार्रवाई मात्र से सारे प्रकरण से संदेह के बादल छंट जाएंगे और लोगों का खंडित भरोसा फिर से कायम हो जाएगा? अब तो संघ प्रमुख ने भी स्वीकारा है कि इस घटनाक्रम से व्यापक हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में अब ट्रस्ट को कठोर फैसले लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए। निस्संदेह, समय रहते यदि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ कड़ी निगाह रखी होती तो यह बड़ा विवाद न खड़ा होता। शुरुआती दौर में जब मामले की सुगबुगाहट सामने आई तो तभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने स्वाभाविक ही हैं। कुछ लोग तो ट्रस्ट को भंग करके नये सिरे से इसके गठन की बात कहते रहे हैं। बहरहाल, इतना तय है कि ट्रस्ट की कारगुजारियों में सबकुछ न तो पारदर्शी था और न ही सब कुछ नियम अनुसार ही चला। कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार थे, जिसके चलते अन्य सदस्य उदासीन बने रहे। यही वजह है कि कुछ लोग एसआईटी से इतर एक उच्च स्तरीय जांच की मांग इस मामले में करते रहे हैं। निस्संदेह, बहुचर्चित चढ़ावा चोरी प्रकरण की गूंज पूरी दुनिया में हुई है, जिसने संघ,भाजपा, केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। यही वजह है कि लोग इस मामले में किसी लीपा-पोती के बजाय भक्तों के दान की पारदर्शी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। जिससे गाहे-बगाहे देश के अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों में भी उठने वाले चंदे में हेरा-फेरी के मामलों का हमेशा के लिये पटाक्षेप हो सके। साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी पता लग सके कि दान की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

कब भरेंगे जानलेवा अंधकूप

> "अम्बाला के मासूम की मौत पूरे देश के लिए गंभीर चेतावनी है। यह केवल शोक मनाने का नहीं, बल्कि व्यवस्था को बदलने का समय है। हर खुला और अनुपयोगी बोरवेल तत्काल बंद होना चाहिए तथा नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

अम्बाला में खुले बोरवेल में गिरने वाले मासूम की मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देश में हादसों से सबक लेने की संस्कृति अब भी विकसित नहीं हो सकी है। यह केवल एक बच्चे की मौत नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर निगरानी और सामाजिक उदासीनता का दुखद परिणाम है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह ऐसी त्रासदी थी, जिसे समय रहते रोका जा सकता था। यदि नियमों का ईमानदारी से पालन होता और अनुपयोगी बोरवेल समय रहते सुरक्षित ढंग से बंद कर दिए जाते, तो शायद एक और परिवार को यह असहनीय पीड़ा न झेलनी पड़ती।

दुर्भाग्य यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रिंस के बोरवेल में गिरने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस समय उम्मीद जगी थी कि अब खुले बोरवेल अतीत की बात बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। हर बार वही दृश्य दोहराया जाता है। एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन युद्धस्तर पर बचाव अभियान चलाते हैं। आधुनिक तकनीक और भारी संसाधन लगाए जाते हैं। पूरा देश प्रार्थना करता है और मीडिया लगातार घटनाक्रम पर नजर रखता है। फिर कुछ दिनों तक चर्चा होती है और मामला धीरे-धीरे सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो जाता है। दुर्भाग्य से अगला हादसा होने तक व्यवस्था भी उसी विस्मृति का हिस्सा बनी रहती है। हादसों को भूल जाने की यही प्रवृत्ति इस समस्या को और गंभीर बनाती जा रही है।

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए कानूनों और दिशा-निर्देशों का अभाव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वर्षों पहले स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि नया बोरवेल खोदने से पहले स्थानीय प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। बोरवेल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा और अनुपयोगी बोरवेल को मिट्टी, रेत तथा कंकड़ से पूरी तरह भरकर स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। मजबूत लोहे का ढक्कन लगाना भी आवश्यक है। राज्यों ने भी समय-समय पर अपने स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद इनका पालन प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा। ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन की निगरानी अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती है। कार्रवाई तब होती है, जब कोई मासूम गड्ढे में गिर चुका होता है। यदि नियमित सर्वेक्षण, प्रभावी निगरानी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तो ऐसे अधिकांश हादसों को पहले ही रोका जा सकता है।

इस समस्या का एक कारण लगातार गिरता भूजल स्तर भी है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में किसान अधिक गहरे बोरवेल खोदने को विवश हैं। लेकिन जब कोई बोरवेल अनुपयोगी हो जाता है, तब उसे वैज्ञानिक तरीके से बंद करने के बजाय कई बार खुला छोड़ दिया जाता है। कुछ पैसे और थोड़ी मेहनत बचाने की यह लापरवाही किसी परिवार के लिए आजीवन दुख का कारण बन सकती है। भूमि मालिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने खेत या परिसर में मौजूद प्रत्येक अनुपयोगी बोरवेल को पूरी तरह सुरक्षित ढंग से बंद करें। यह केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व भी है।

वास्तव में सिर्फ प्रशासन को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं होगा। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि किसी गांव, खेत या खाली जमीन पर खुला बोरवेल दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को समय-समय पर ऐसे बोरवेल का सर्वेक्षण कराना चाहिए। स्कूलों और पंचायत स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग संभावित खतरे को गंभीरता से लें। दुर्घटना के बाद शोक व्यक्त करने से कहीं अधिक जरूरी दुर्घटना से पहले सावधानी बरतना है।

अब समय केवल संवेदना, मुआवजे और औपचारिक बैठकों तक सीमित रहने का नहीं है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें जवाबदेही स्पष्ट हो और नियमों की अनदेखी पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जहां भी असुरक्षित और खुला बोरवेल मिले, वहां जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जवाबदेही तय किए बिना नियम केवल कागजों तक सीमित रहेंगे और हर नया हादसा हमारी प्रशासनिक विफलता का प्रमाण बनता रहेगा।

अम्बाला के मासूम की मौत पूरे देश के लिए गंभीर चेतावनी है। यह केवल शोक मनाने का नहीं, बल्कि व्यवस्था को बदलने का समय है। हर खुला और अनुपयोगी बोरवेल तत्काल बंद होना चाहिए तथा नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। विकास और कृषि की जरूरतों के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि अपने सबसे कमजोर नागरिकों की सुरक्षा से होती है। यदि अब भी हमने सबक नहीं लिया, तो हर अगली ऐसी मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक विफलता मानी जाएगी।

प्रेरणा

समय के सामने झुकता हर साम्राज्य

इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाते हैं, तो उनमें केवल विजयों, पराजयों और साम्राज्यों की कहानियाँ ही नहीं मिलतीं, बल्कि मनुष्य के अभिमान और समय की सर्वोच्च सत्ता का भी स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। हर युग में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर विशाल साम्राज्य खड़े किए। उन्हें लगा कि उनकी इच्छा ही कानून है और उनका निर्णय ही अंतिम सत्य है। लेकिन समय ने बार-बार यह सिद्ध किया कि संसार का सबसे बड़ा शासक कोई राजा, सम्राट या विजेता नहीं, बल्कि स्वयं समय है। समय के सामने सबसे ऊँचे सिंहासन भी छोटे पड़ जाते हैं और सबसे बड़ी सेनाएँ भी असहाय दिखाई देती हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में समय को काल, महाकाल और ईश्वर की व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। वह न किसी का पक्ष लेता है और न किसी से शत्रुता करता है। उसका एक ही धर्म है—सत्य को स्थापित करना और अहंकार को मिटाना। प्राचीन भारत में विंध्याचल पर्वत के निकट एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र अपनी वीरता, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। वर्षों तक उन्होंने अनेक युद्ध जीते, सीमाओं का विस्तार किया और पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनकी सेना अनुशासित थी, खजाना भरा हुआ था और प्रजा भी समृद्ध थी। धीरे-धीरे पूरे राज्य में यह धारणा बन गई कि राजा वीरेंद्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं राजा भी यही मानने लगे कि उनका भाग्य सदैव उनका साथ देगा। दरबार में प्रतिदिन उनकी प्रशंसा होती, कवि उन्हें धरती का देवता बताते और मंत्री उनकी दूरदर्शिता के गुण गाते। निरंतर सफलता ने उनके भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया जो धीरे-धीरे विनम्रता को पीछे छोड़कर अभिमान में बदलने लगा।

एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। वे किसी प्रकार की भिक्षा नहीं माँगते थे और न ही किसी राजसी सम्मान की इच्छा रखते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जब राजा को उनके आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने उन्हें दरबार में बुलाया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर पूछा, "राजन, सुना है आपके राज्य में सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। क्या यह बात सत्य है?" राजा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, "मेरे आदेश के बिना इस राज्य में कोई निर्णय नहीं होता। मेरी सेना अजेय है और मेरा शासन अटल है।" साधु ने दूसरा प्रश्न किया, "यदि ऐसा है तो क्या आप वर्षा को रोक सकते हैं? क्या आप अपने वृद्ध होते शरीर को युवा बनाए रख सकते हैं? क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाला कल आपके अनुसार ही घटित होगा?"

राजा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने स्वीकार किया, "नहीं, प्रकृति और समय पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता।"

साधु ने शांत स्वर में कहा, "जिस पर समय का अधिकार हो, वह स्वयं को संसार का स्वामी कैसे कह सकता है? राजसत्ता मनुष्य को शासन करने का अवसर देती है, लेकिन समय यह बताता है कि वह अवसर कब तक रहेगा। इसलिए सत्ता का आनंद लीजिए, लेकिन उसे अपना स्थायी अधिकार मत समझिए।"

राजा ने साधु की बात सुन तो ली, किंतु उसे सामान्य उपदेश मानकर भूल गए। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता किसी भी संकट का सामना कर सकती है। वे पहले की तरह विजय अभियान चलाते रहे। राज्य का विस्तार होता गया और उनके अभिमान की दीवार भी ऊँची होती गई। उन्हें विश्वास था कि उनका साम्राज्य आने वाली अनेक पीढ़ियों तक अडिग रहेगा।

लेकिन समय की चाल मनुष्य की योजनाओं से कहीं अधिक गहरी होती है। कुछ वर्षों बाद लगातार वर्षा न होने के कारण राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियाँ सिकुड़ गईं और अन्न के भंडार खाली होने लगे। इसी बीच सीमावर्ती राज्यों ने विद्रोह कर दिया। सेना, जो कभी अपराजेय मानी जाती थी, अब भूख और संसाधनों की कमी से कमजोर पड़ने लगी। जिन लोगों ने कभी राजा की जय-जयकार की थी, वे अब अपने परिवारों के जीवन की चिंता में डूब गए। राजा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियाँ उनके नियंत्रण से बाहर थीं। उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि सत्ता होने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ मनुष्य के हाथ में है।

एक रात राजा अकेले राजमहल की छत पर बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें वही साधु याद आए। उनके शब्द मानो हवा के साथ लौटकर उनके कानों में गूँजने लगे—"समय ही सबसे बड़ा शासक है।" अगले ही दिन राजा ने साधु को खोजने का आदेश दिया। कई दिनों की खोज के बाद साधु एक नदी के किनारे ध्यानमग्न मिले। राजा स्वयं उनके पास पहुँचे। इस बार उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि अनुभव की विनम्रता थी।

राजा ने साधु से कहा, "मैंने अनेक युद्ध जीते, अनेक राज्यों पर अधिकार किया, लेकिन आज समझ आया कि सबसे कठिन युद्ध अपने अहंकार से होता है। मैं सोचता था कि मेरी शक्ति असीम है, पर समय ने मुझे मेरी सीमा दिखा दी।" साधु मुस्कुराए और बोले, "यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति समय की शक्ति को पहचान लेता है, वह कभी अहंकारी नहीं बनता। उसे पता होता है कि सफलता स्थायी नहीं और कठिनाई भी अनंत नहीं। समय दोनों को बदलता रहता है।"

राजा ने उसी दिन से अपने शासन की दिशा बदल दी। उन्होंने विजय अभियानों को रोककर प्रजा के कल्याण पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने जलाशयों का निर्माण कराया, किसानों की सहायता की, अन्न भंडारों की व्यवस्था की और राज्य में ऐसे नियम बनाए जिनसे भविष्य की कठिनाइयों का सामना किया जा सके। धीरे-धीरे राज्य फिर समृद्ध होने लगा। इस बार राजा की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता बन गई। लोग उन्हें केवल विजेता नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक के रूप में याद करने लगे।

यह कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कहानी है। आज कोई अपने पद पर गर्व करता है, कोई अपने धन पर, कोई अपनी प्रसिद्धि पर और कोई अपनी प्रतिभा पर। लेकिन समय की एक करवट इन सबकी दिशा बदल सकती है। इसलिए जीवन में सफलता मिलने पर विनम्र रहना उतना ही आवश्यक है जितना कठिन समय में धैर्य बनाए रखना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से तय होता है। धन समाप्त हो सकता है, सत्ता छिन सकती है, यश फीका पड़ सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध समय भी समाप्त नहीं कर सकता। इतिहास उन्हीं लोगों को सम्मान देता है जिन्होंने शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं, बल्कि सेवा को चुना और सफलता मिलने पर विनम्रता का दामन नहीं छोड़ा।

Mayawati की जमीन पर Akhilesh Yadav की एंट्री, UP में बड़ा खेल शुरू, सपा के Dalit Card से BJP भी हैरान

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है, जिसने बहुजन समाज पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है और भारतीय जनता पार्टी को भी माथा खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ टिकट बांटने की नहीं है, बल्कि उस नई सामाजिक बिसात की है, जिस पर अखिलेश यादव अब दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण को नए अंदाज में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में लगभग सौ दलित उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मौका देने की रणनीति शामिल है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक जमीन पर सेंध लगानी है तो केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, बल्कि टिकट वितरण में भी साहस दिखाना होगा।

दरअसल, यह पूरी कवायद उस बदले हुए राजनीतिक माहौल का नतीजा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपने पुराने प्रभाव से दूर होती दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला और उसका मत प्रतिशत भी तेजी से नीचे आया। उधर समाजवादी पार्टी ने यह समझ लिया है कि अगर दलित मतदाता का एक हिस्सा भी उसके साथ मजबूती से आ गया, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता और आसान हो सकता है।

इसी सोच के तहत पार्टी अब आरक्षित सीटों तक सीमित रहने की बजाय सामान्य सीटों पर भी दलित प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जहां समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, वहां दलित उम्मीदवारों को उतारकर नया सामाजिक समीकरण बनाया जाएगा। यानी जहां जमीन कमजोर है, वहां जातीय गणित से जीत का पुल तैयार करने की कोशिश होगी।

दिलचस्प बात यह है कि यह प्रयोग पूरी तरह नया भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई दलित उम्मीदवार उतारे थे और उसका फायदा भी मिला। अयोध्या, मेरठ और फैजाबाद जैसी सीटों पर पार्टी ने दलित चेहरों को मौका देकर राजनीतिक संदेश दिया था कि अब पार्टी केवल यादव मुस्लिम पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहती।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव अब उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को केवल यादव और मुस्लिम मतों की पार्टी माना जाता था। यही कारण है कि पार्टी अब दलित समाज में लगातार संवाद बढ़ा रही है। पंचायत स्तर से लेकर विधान परिषद तक प्रतिनिधित्व का नया खाका तैयार किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी के भीतर भी यह समझ बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने से जो राजनीतिक खालीपन बना है, उसे भरने का यह सबसे सही समय है। पार्टी नेताओं का दावा है कि दलित समाज का एक हिस्सा अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। ऐसे में अगर सम्मानजनक भागीदारी दी जाए, तो यह वर्ग स्थायी रूप से नए गठजोड़ की तरफ आ सकता है। उधर, भारतीय जनता पार्टी भी इस बदलते समीकरण को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। भाजपा को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाता सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि चुनावी दिशा तय करने वाला निर्णायक वर्ग है। इसी कारण भाजपा लगातार अपने दलित संपर्क अभियान को तेज कर रही है और यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका सामाजिक विस्तार अभी भी कायम है।

बहुजन समाज पार्टी के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। कभी दलित राजनीति की सबसे बड़ी धुरी रही पार्टी अब दो तरफा दबाव में है। एक तरफ भाजपा उसका परंपरागत वोट बैंक खींच रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नए अंदाज में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

राजनीति के पुराने खिलाड़ी मानते हैं कि यह पूरा खेल केवल टिकटों का नहीं, बल्कि प्रतीकों और संदेशों का है। अखिलेश यादव यह जताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं रही। वहीं भाजपा यह साबित करने में जुटी है कि उसका सामाजिक समीकरण अभी भी सबसे व्यापक है। और बहुजन समाज पार्टी इस कोशिश में लगी है कि उसका कोर मतदाता पूरी तरह छिटकने न पाए।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नया दौर बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब चुनावी मंचों पर केवल विकास और वादों की बात नहीं होगी, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की नई पटकथा भी लिखी जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि दलित राजनीति अब केवल एक पार्टी की जागीर नहीं रही। साइकिल, कमल और हाथी तीनों अब उसी मैदान में उतर चुके हैं, जहां हर वोट के पीछे पूरा सामाजिक गणित छिपा है।

अभियान

दिव्य चेतना के महायोगी : ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा का अलौकिक और प्रेरणादायी जीवन

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यहाँ केवल राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों ने ही इतिहास नहीं बनाया, बल्कि संतों, ऋषियों और महायोगियों ने भी समाज की आत्मा को दिशा दी। जब-जब संसार भौतिकता, अहंकार और स्वार्थ की ओर बढ़ा, तब-तब किसी न किसी संत ने अपने तप, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति से मानवता को सत्य, प्रेम और ईश्वर की ओर लौटने का मार्ग दिखाया। ऐसे ही अद्भुत संतों की परंपरा में ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन जितना रहस्यमय था, उतना ही प्रेरणादायक भी। वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ईश्वर के साक्षात स्वरूप, योगसिद्ध महापुरुष और सनातन आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी दिव्यता थी कि जो भी उनके संपर्क में आता, वह स्वयं को किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति में अनुभव करता था।

देवराहा बाबा का जीवन अनेक रहस्यों से घिरा रहा। उनके जन्म, परिवार, प्रारंभिक जीवन और आयु के विषय में कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को लेकर अनेक मान्यताएँ प्रचलित रहीं। स्वयं बाबा ने कभी अपने जन्म या वंश के विषय में कोई दावा नहीं किया। जब उनके निकटस्थ भक्तों ने उनसे उनके प्राकट्य के विषय में पूछा, तब उन्होंने संकेतपूर्ण शब्दों में कहा था कि उनकी उत्पत्ति जल से हुई है। उन्होंने एक अवसर पर अपने भक्तों से यह भी कहा, "मैं तुम लोगों की तरह मनुष्य नहीं हूँ। यह शरीर मैंने केवल तुम्हारे कल्याण के लिए धारण किया है। जो मुझे केवल शरीर मानता है, वह सत्य को नहीं जानता।" इन वचनों को उनके अनुयायी उनके आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मानते हैं। यद्यपि इन कथनों का ऐतिहासिक सत्यापन संभव नहीं है, फिर भी उनके भक्त इन्हें उनकी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक मानते हैं।

ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा की आयु भी एक रहस्य बनी रही। अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास था कि उन्होंने अत्यंत दीर्घकाल तक इस धरती पर निवास किया। कुछ लोगों ने उनकी आयु दो सौ वर्ष से अधिक बताई, तो कुछ ने इससे भी अधिक होने का दावा किया। किंतु स्वयं बाबा ने कभी अपनी आयु के विषय में कोई चर्चा नहीं की। उनके लिए शरीर केवल साधना का माध्यम था, लक्ष्य नहीं। इसलिए उन्होंने कभी अपनी सिद्धियों या दीर्घायु का प्रचार नहीं किया। यही विनम्रता उन्हें अन्य संतों से अलग पहचान देती है।

'देवराहा बाबा' नाम के संबंध में भी विभिन्न मान्यताएँ प्रचलित हैं। व्यापक रूप से माना जाता है कि उनका संबंध उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से रहा और इसी कारण उन्हें 'देवराहा बाबा' कहा जाने लगा। देवरिया जिले के लार रोड के समीप सरयू नदी के तट पर स्थित उनका आश्रम वर्षों तक लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहा। यद्यपि उनके जीवन का अधिकांश भाग रहस्य में ढका रहा, लेकिन उनका आश्रम आध्यात्मिक चेतना का जीवंत केंद्र बन गया था।

देवराहा बाबा का व्यक्तित्व अत्यंत सादा और तपस्वी था। उनकी दुबली-पतली काया, कमर में मृगचर्म, कंधे पर यज्ञोपवीत, लंबी जटाएँ और तेजस्वी मुखमंडल उन्हें सामान्य संतों से अलग पहचान देते थे। वे अधिकांश समय सरयू नदी के किनारे लकड़ी के ऊँचे मचान पर निवास करते थे। वहीं से वे अपने भक्तों को दर्शन देते, आशीर्वाद प्रदान करते और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे। उनका जीवन विलासिता से पूर्णतः दूर था। उन्होंने कभी राजसी आश्रम, भव्य भवन या भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं की। उनके लिए प्रकृति ही आश्रम थी और ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा वैभव।

उनके आश्रम में प्रतिदिन हजारों लोग केवल एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी, अधिकारी, उद्योगपति, कलाकार, न्यायाधीश, सैनिक और देश के अनेक प्रमुख राजनेता भी उनके दर्शन के लिए आते थे। भारत ही नहीं, विदेशों से भी अनेक श्रद्धालु उनके पास आध्यात्मिक शांति की खोज में पहुँचते थे। उनके भक्तों का विश्वास था कि बाबा किसी व्यक्ति से कुछ पूछे बिना ही उसके जीवन की परिस्थितियों, उसके मन की स्थिति और उसकी समस्याओं को जान लेते थे। यह विश्वास उनके आध्यात्मिक प्रभाव का प्रमुख आधार बन गया था। यद्यपि ऐसी मान्यताओं का वस्तुनिष्ठ प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनके अनुयायियों के अनुभवों ने उन्हें लोकविश्वास का हिस्सा बना दिया।

देवराहा बाबा का सबसे बड़ा संदेश था—सरल जीवन, निर्मल विचार और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। वे बाहरी आडंबरों से दूर रहकर आंतरिक शुद्धता पर बल देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य यदि अपने मन को स्वार्थ, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त कर ले, तो वही सबसे बड़ी साधना है। वे किसी एक पंथ, संप्रदाय या मत का प्रचार नहीं करते थे। उनके पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाता था। उनके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म थी और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा।

बाबा का आश्रम केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक संवाद का स्थान भी था। वहाँ आने वाले लोगों को जीवन की समस्याओं का समाधान केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि उनके मौन और स्नेहपूर्ण व्यवहार से भी मिलता था। अनेक लोग केवल उनके दर्शन करके ही मानसिक शांति का अनुभव करते थे। उनके भक्तों का विश्वास था कि बाबा के आशीर्वाद से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। यही कारण था कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के उनके चरणों में उपस्थित होते थे।

सरयू नदी के तट पर बने उनके लकड़ी के मचान से जुड़ी अनेक लोककथाएँ भी प्रचलित हैं। श्रद्धालुओं के बीच यह मान्यता रही कि वर्षा ऋतु में जब सरयू नदी उफान पर होती थी, तब भी पानी उनके मचान को स्पर्श कर शांत हो जाता था। यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है, जिसे उनके अनुयायी उनकी आध्यात्मिक महिमा से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इन घटनाओं का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु लोकआस्था में इनका विशेष स्थान है।

देवराहा बाबा की विशेषता यह भी थी कि उन्होंने कभी स्वयं को चमत्कारों का केंद्र नहीं बनाया। वे बार-बार अपने भक्तों को ईश्वर, भक्ति, सदाचार और सेवा की ओर प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा चमत्कार उसका चरित्र है। यदि व्यक्ति सत्य, करुणा और संयम का पालन करता है, तो उसका जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि उनके उपदेशों में नैतिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है।

उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग 'देवराहा बाबा दिव्य-दर्शन' नामक ग्रंथ के प्रकाशन से जुड़ा है। कुछ विद्वान भक्तों ने उनके उपदेशों और विचारों का संकलन कर पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया। जब उन्होंने बाबा से अनुमति माँगी, तब बाबा ने कुछ स्पष्ट शर्तें रखीं। उन्होंने कहा कि पुस्तक पर किसी व्यक्ति का नाम संपादक के रूप में प्रकाशित न किया जाए, क्योंकि ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुस्तक के प्रकाशन के लिए किसी प्रकार का चंदा न लिया जाए और न ही उसका कोई मूल्य निर्धारित किया जाए। यह ग्रंथ केवल प्रसाद के रूप में लोगों तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तक में किसी मत, संप्रदाय या विचारधारा का खंडन न किया जाए और न ही उसमें भाषा, जाति, प्रांत, राजनीति या किसी प्रकार के सामाजिक विभाजन की भावना का समावेश हो। उनके इन निर्देशों से स्पष्ट होता है कि वे समाज को जोड़ने वाले संत थे, विभाजन पैदा करने वाले नहीं।

जब पुस्तक उनके निर्देशों के अनुसार प्रकाशित हुई, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं अपने हाथों से उसे श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप प्रदान करने लगे। यह घटना उनके व्यक्तित्व की विनम्रता और निष्काम भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने नाम, प्रसिद्धि या प्रचार की इच्छा नहीं की। उनके लिए ज्ञान का उद्देश्य केवल लोककल्याण था।

ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा ने 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर अपनी देहलीला का समापन किया। उनके महाप्रयाण के बाद भी उनका आश्रम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज भी देश-विदेश से लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मानसून का कहर: वायनाड में भूस्खलन, मुंबई में जलसैलाब डोडा में फ्लैश फ्लड... देशभर में बारिश बनी बड़ी चुनौती

नई दिल्ली। देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, लेकिन इस बार बारिश राहत से कहीं अधिक आफत लेकर आई है। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से लेकर पर्वतीय राज्यों तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। केरल के वायनाड में भीषण भूस्खलन, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नालासोपारा और वसई-विरार में जलभराव, गुजरात के सूरत में सड़कों और अंडरपास का डूब जाना तथा जम्मू-कश्मीर के डोडा में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं ने एक बार फिर देश के आपदा प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सबसे चिंताजनक तस्वीर केरल के वायनाड जिले से सामने आई, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क किनारे खड़े लोग अचानक पहाड़ी से तेज गति से नीचे आता मिट्टी, पत्थर और मलबे का विशाल प्रवाह देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका मलबे से भर जाता है और वहां खड़े कई वाहन उसकी चपेट में आ जाते हैं। एक भारी-भरकम टैंकर भी मलबे के तेज बहाव के सामने पूरी तरह बेबस दिखाई देता है। इस दृश्य ने लोगों को पिछले वर्ष वायनाड में आई भीषण त्रासदी की याद दिला दी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा उस क्षेत्र में हुआ, जहां मलप्पुरम-वायनाड टनल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि सुरंग निर्माण के दौरान निकाली गई बड़ी मात्रा में मिट्टी को सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना पास ही ढेर के रूप में जमा कर दिया गया था। लगातार बारिश के कारण यह मिट्टी पानी के साथ बहकर नीचे आ गई और उसने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। राज्य सरकार के अनुसार हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि अनेक लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के लापता होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस, दमकल विभाग, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की भी मदद ली जा रही है।

इस घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ सप्ताह पहले ही संबंधित एजेंसियों को निर्माण स्थल पर जमा अतिरिक्त मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि संबंधित ठेकेदार ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। यदि जांच में यह तथ्य सही साबित होता है तो यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही का भी गंभीर मामला माना जाएगा। राज्य सरकार ने पूरे घटनाक्रम की जांच के संकेत दिए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करने की बात कही है। अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार, प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने से बचने की सलाह दी है।

वायनाड पहले भी भूस्खलन की भयावह त्रासदी झेल चुका है। वर्ष 2024 में यहां हुए विनाशकारी भूस्खलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए थे। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि वायनाड का बड़ा हिस्सा अत्यंत संवेदनशील पहाड़ी ढलानों पर स्थित है, जहां लगातार वर्षा के दौरान मिट्टी की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्यों के दौरान वैज्ञानिक मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनियंत्रित निर्माण, जंगलों की कटाई और ढलानों पर अतिरिक्त भार भविष्य में ऐसे हादसों की आशंका और बढ़ा सकते हैं।

उधर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर मानसून की मार से जूझती नजर आई। लगातार दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर की रफ्तार लगभग थम गई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार पिछले 48 घंटों में शहर के कई हिस्सों में लगभग 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी वर्षा के चलते कई प्रमुख सड़कें, रेलवे ट्रैक और निचले इलाके जलमग्न हो गए। अनेक स्थानों पर घंटों तक यातायात बाधित रहा और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मुंबई के अलावा नालासोपारा, वसई-विरार और आसपास के उपनगरों में भी जलभराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली। कई आवासीय कॉलोनियों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया। अनेक कारें और दोपहिया वाहन पानी में आधे से अधिक डूबे दिखाई दिए। स्थानीय लोगों को घरों से निकलने और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी तक में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पेड़ गिरने और सड़क धंसने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे यातायात और अधिक प्रभावित हुआ।

बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों ने एक बार फिर मुंबई की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद शहर में थोड़ी ही देर की तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मानसून आते ही हर साल यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण, नालों पर अतिक्रमण और जल निकासी व्यवस्था के आधुनिकीकरण में देरी के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

महाराष्ट्र के पुणे में भी लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। एक स्थान पर सड़क पर अत्यधिक जलभराव होने के कारण एक यात्री बस बीच रास्ते में फंस गई। सूचना मिलने पर राहत दल मौके पर पहुंचा और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं, अलंदी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

गुजरात के सूरत में भी लगातार वर्षा के कारण कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। अनेक अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गए, जिससे यातायात रोकना पड़ा। निचले क्षेत्रों में स्थित घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन ने जल निकासी के लिए पंपिंग मशीनों की सहायता ली और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के ठठरी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने भी व्यापक नुकसान पहुंचाया। पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ आए पत्थर, मिट्टी और मलबे ने कई दुकानों, वाहनों और मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

भारतीय मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

मानसून की शुरुआती बारिश ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केवल मौसम पूर्वानुमान पर्याप्त नहीं है। शहरी नियोजन, वैज्ञानिक निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन और प्रभावी आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किए बिना हर वर्ष ऐसी त्रासदियों दोहराए जाने का खतरा बना रहेगा। फिलहाल देश के कई राज्यों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है, जबकि करोड़ों लोगों की निगाहें अब मौसम के अगले दौर पर टिकी हैं। यदि आने वाले दिनों में बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो कई क्षेत्रों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए समय रहते प्रभावी तैयारी, त्वरित राहत और दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट - 2008 के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक जीत : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▶▶ भारत की धरती पर आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▶▶ आतंकवाद के खिलाफ देश की बहुत बड़ी कानूनी जीत : हाईकोर्ट ने 38 आतंकवादियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

▶▶ गुजरात और भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, यह मजबूत फैसला देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा

▶▶ मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार तत्काल प्रदान करेगी

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को गिफ्ट सिटी गांधीनगर से वर्ष-2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस दिन को देश के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन कहा। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि यह फैसला केवल अहमदाबाद या गुजरात के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के सभी शांतिप्रिय देशों के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा और मजबूत संदेश है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। आज उन सभी निर्दोष आत्माओं, उनके परिवारों और नागरिकों को सच्चा न्याय मिला है। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और 11 आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। श्री संघवी ने गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से हाईकोर्ट, निचली अदालत तथा पूरी जांच टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने जोड़ा कि यह मजबूत न्याय दिलाने के पीछे जांच टीम ने वर्षों तक बिना किसी कानूनी त्रुटि या समझौते के दिन-रात मेहनत कर जो सराहनीय कार्य किया है, वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह फैसला स्पष्ट रूप से साबित करता है कि भारत की धरती पर आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फैसले के तहत इस ब्लास्ट में जान गंवाने वाले निर्दोष मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता तथा जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का जो आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, उसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार संवेदनशीलता के साथ तत्काल प्रभाव से लागू कर भुगतान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी है ।

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से जून, 2026 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से लगभग 69 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व संग्रह में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

पश्चिम रेलवे द्वारा रेल राजस्व की सुरक्षा तथा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अप्रैल से जून, 2026 की अवधि के दौरान अपने समूचे नेटवर्क पर व्यापक एवं गहन टिकट जांच अभियान निरंतर चलाए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में पश्चिम रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए रेलवे राजस्व की सुरक्षा तथा अनुशासित यात्रा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ किया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की सक्रिय निगरानी में टिकट जांच कर्मचारियों की अत्यंत प्रेरित टीम ने मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में व्यापक टिकट जांच अभियान चलाए। इन सतत अभियानों का उद्देश्य राजस्व की हानि को रोकना, अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाना तथा वैध यात्रियों को निर्बाध एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना था। अप्रैल से जून, 2026 की अवधि के दौरान बिना बुक किए गए सामान के मामलों सहित 9.50 लाख से अधिक बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों का पता लगाया गया, जिससे लगभग 69 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में वसूले गए लगभग 59 करोड़ रुपये की तुलना में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। केवल जून, 2026 के दौरान ही 2.65 लाख बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों का पता लगाया गया, जिससे लगभग 18.50 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। यह राशि जून, 2025 में वसूले गए 15.24 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 21.30 प्रतिशत अधिक है।

मुंबई उपनगरीय खंड में भी गहन टिकट जांच अभियानों के उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए। अप्रैल से जून, 2026 की अवधि में बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के 3.14 लाख मामलों का पता लगाया गया, जिससे लगभग 16.50 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में वसूले गए 15.90 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है, जो उपनगरीय नेटवर्क में अनुशासित एवं अधिकृत यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में पश्चिम रेलवे के सतत प्रयासों को दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा एसी उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सामान्य टिकट धारकों द्वारा अनधिकृत यात्रा को रोकने के लिए भी विशेष टिकट जांच अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। अप्रैल से जून, 2026 के दौरान एसी उपनगरीय सेवाओं में 49,550 दंडात्मक मामलों का पता लगाया गया, जिससे 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में वसूले गए 62.76 लाख रुपये की तुलना में लगभग 160 प्रतिशत की वृद्धि है।

ये उत्साहवर्धक परिणाम राजस्व की हानि को रोकने, यात्रियों में अनुशासन बनाए रखने तथा रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग के सतत प्रयासों एवं समर्पण को प्रतिबिंबित करते हैं।

पश्चिम रेलवे आम जनता से उचित एवं वैध टिकट लेकर यात्रा करने की अपील करती है।

दही फेशियल से पाएं प्राकृतिक निखार, बरसात में त्वचा की देखभाल का आसान और असरदार तरीका : शहनाज़ हुसैन

बरसात का मौसम जहां वातावरण को ठंडक और ताजगी देता है, वहीं त्वचा के लिए कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आता है। बढ़ी हुई नमी, धूल, प्रदूषण और त्वचा पर अतिरिक्त तेल जमा होने से चेहरे की प्राकृतिक चमक कम होने लगती है। ऐसे मौसम में त्वचा की सही देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज़ हुसैन के अनुसार, यदि महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की बजाय घर में उपलब्ध प्राकृतिक चीजों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो त्वचा को स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनाए रखा जा सकता है। इन्हीं घरेलू उपायों में दही सबसे प्रभावी और सुरक्षित प्राकृतिक सौंदर्य सामग्री मानी जाती है।

भारतीय घरों में सदियों से दही का उपयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं, बल्कि सौंदर्य निखारने के लिए भी किया जाता रहा है। दही में मौजूद प्राकृतिक लैक्टिक एसिड त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ, कोमल और दमकती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-बी, विटामिन-डी तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को भीतर से पोषण देने का काम करते हैं। शहनाज़ हुसैन का कहना है कि बरसात के मौसम में जब लोग दही का सेवन अपेक्षाकृत कम कर देते हैं, तब इसका उपयोग फेस केयर रूटीन में शामिल करना त्वचा के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।

दही एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह भी काम करता है। यह चेहरे पर जमी धूल, प्रदूषण, अतिरिक्त तेल और अशुद्धियों को धीरे-धीरे साफ करता है, बिना त्वचा की प्राकृतिक नमी छीने। इसके लिए दो चम्मच गाढ़े दही में दो चम्मच गुलाब जल मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। इस मिश्रण से चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से गोलाकार गति में कुछ मिनट तक मालिश करें। इसके बाद ताजे पानी से चेहरा धो लें। यह प्रक्रिया त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसे ताजगी और प्राकृतिक चमक भी प्रदान करती है।

यदि त्वचा का रंग धूप के कारण मटमैला हो गया हो या टैनिंग की समस्या हो, तो दही और बेसन का फेस पैक बेहद लाभदायक माना जाता है। दो चम्मच दही में एक चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी और कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर मुलायम पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाकर प्राकृतिक रूप से सूखने दें। लगभग 15 से 20 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से त्वचा का रंग साफ दिखाई देने लगता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार आने लगता है।

त्वचा की नमी बनाए रखने और उसे मुलायम बनाने के लिए दही के साथ एलोवेरा जेल का मिश्रण भी अत्यंत उपयोगी है। एक चम्मच दही में एक चम्मच एलोवेरा जेल और कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाकर तैयार किया गया फेस पैक त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है। इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाने के बाद ठंडे पानी से धो लेने पर त्वचा तरोताजा महसूस होती है। यह मिश्रण दाग-धब्बों, हल्के पिंपल्स और त्वचा की रूखापन जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक माना जाता है।

यदि त्वचा अत्यधिक शुष्क है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है, तो दही और बादाम तेल का मिश्रण बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पांच चम्मच दही में दो चम्मच बादाम का तेल मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, जब तक कि यह क्रीम जैसा न बन जाए। इस मिश्रण से चेहरे, गर्दन और कंधों की हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद गर्म पानी में भीगे मुलायम सूती कपड़े से त्वचा को धीरे-धीरे साफ करें। इससे त्वचा को गहराई से पोषण मिलता है और उसमें नई ताजगी महसूस होती है।

चेहरे की प्राकृतिक चमक बढ़ाने के लिए दही, शहद, हल्दी और नींबू का मिश्रण भी काफी प्रभावी माना जाता है। आधा कप सादा दही, एक बड़ा चम्मच शहद, एक चम्मच नींबू का रस और एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाकर चिकना पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़कर पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। लगभग 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें और मुलायम तौलिये से त्वचा को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। यह फेस पैक त्वचा को प्राकृतिक चमक देने के साथ-साथ उसे मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है।

तैलीय त्वचा वाले लोगों के लिए दही विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। एक चम्मच बेसन और एक चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसमें दो बूंद नींबू का रस और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। इस मिश्रण को साफ चेहरे और गर्दन पर लगाकर सूखने दें। लगभग 20 से 30 मिनट बाद हल्का गुनगुना पानी लगाकर फेस पैक को नरम करें और फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ करें। इससे त्वचा पर जमा मृत कोशिकाएं निकल जाती हैं और अतिरिक्त तेल भी नियंत्रित होता है। अंत में ठंडे पानी से चेहरा धोने पर त्वचा ताजा और साफ महसूस होती है।

शहनाज़ हुसैन के अनुसार, किसी भी फेशियल का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसकी सभी प्रक्रियाएं सही क्रम में की जाएं। सबसे पहले चेहरे की अच्छी तरह क्लींजिंग करनी चाहिए, ताकि धूल और गंदगी हट जाए। इसके बाद हल्की स्क्रबिंग करके मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाना जरूरी है। फिर हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा को पोषण मिलता है। अंत में फेस पैक लगाकर त्वचा को आराम देना चाहिए।

फेशियल पूरा होने के बाद त्वचा की मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आपकी त्वचा रूखी है तो एलोवेरा जेल या हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं, जबकि तैलीय त्वचा वाले लोग प्राकृतिक टोनर के रूप में गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। इससे त्वचा का पीएच संतुलन बना रहता है और रोमछिद्र भी साफ रहते हैं।

दही फेशियल का नियमित उपयोग त्वचा को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है। इससे त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ती है, लंबे समय तक नमी बनी रहती है, सनटैन और सनबर्न का प्रभाव कम होता है तथा झाइयां, पिंपल्स और मुंहासों की समस्या में भी राहत मिल सकती है।

वडोदरा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार के सिविल वर्क के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने रेल परिचालन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पिछले दिनों वडोदरा स्टेशन पर व्यापक सिग्नलिंग अपग्रडेशन तथा यार्ड री-मॉडलिंग कार्य सफलतापूर्वक लगभग पूर्ण कर लिया है। 34 वर्ष पुरानी सीमेंस निर्मित रूट रिले इंटरलॉकिंग यानि RRI प्रणाली को हटाकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानि EI प्रणाली स्थापित की गई, जिसका सफल कमीशनिंग 01 जुलाई 2026 को किया गया। वर्तमान में प्लेटफार्म संख्या 4 & 5 के एक्सटेंशन का सिविल वर्क जारी है, जिसके लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, फलस्वरूप कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पोस्ट नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के अंतर्गत प्लेटफार्म संख्या 4 & 5 के एक्सटेंशन के सिविल वर्क इत्यादि कार्य के लिए ब्लॉक लिया जायेगा, फलस्वरूप कुछ निम्न ट्रेनों के अस्थायी रूप से विश्वामित्री (VS), बाजवा (BJW), छायापुरी (CYI), प्रतापनगर (PRTN) एवं मकरपुरा (MPR)स्टेशनों पर शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन को 10 जुलाई, 2026 तक विस्तार दिया जाएगा।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है :

शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन ट्रेनें :-

1. ट्रेन संख्या 19819 वडोदरा–कोटा एक्सप्रेस दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन संख्या 19820 कोटा–वडोदरा एक्सप्रेस दिनांक 08 और 09 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन संख्या 19036 अहमदाबाद–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
4. ट्रेन संख्या 19035 वडोदरा–अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
5. ट्रेन संख्या 69117 वडोदरा–दाहोद मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
6. ट्रेन संख्या 69119 वडोदरा–दाहोद मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
7. ट्रेन संख्या 69121 वडोदरा–गोधरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
8. ट्रेन संख्या 69101 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
9. ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
10. ट्रेन संख्या 69113 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
11. ट्रेन संख्या 69107 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।

12 ट्रेन संख्या 69109 सूरत–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा विश्वामित्री–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

13. ट्रेन संख्या 69111 सूरत–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा विश्वामित्री–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
14. ट्रेन संख्या 69122 गोधरा–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
15. ट्रेन संख्या 69120 दाहोद–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
16. ट्रेन संख्या 69118 गोधरा–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
17. ट्रेन संख्या 69114 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
18. ट्रेन संख्या 69108 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
19. ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
20. ट्रेन संख्या 12930 वडोदरा–वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शाम 16:45 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा स्टेशन पर 17:05/17:10 तक 5 मिनट स्टॉपेज होगा।
21. ट्रेन संख्या 59049 वलसाड–वडोदरा पैसेंजर ट्रेन दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को मकरपुरा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा मकरपुरा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
22. ट्रेन संख्या 59050 वडोदरा–वलसाड पैसेंजर ट्रेन दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को मकरपुरा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजनेट की जाएगी तथा वडोदरा-मकरपुरा के बीच निरस्त रहेगी।

23 ट्रेन संख्या 59549 वडोदरा–वटवा पैसेंजर ट्रेन दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को प्रतापनगर स्टेशन से सुबह 5:40 बजे शॉर्ट ओरिजनेट की जाएगी तथा वडोदरा स्टेशन पर 06:25/06:30 तक 5 मिनट का ठहराव होगा।

24. ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
25. ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 09 और 10 जुलाई 2026 को बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है :

पश्चिम रेलवे
अहमदाबाद मण्डल

शुद्धिपत्र

निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 के संबंध में शुद्धिपत्र; ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 दिनांक 09/06/2026; कार्य का नाम: सीपीओएच अहमदाबाद (ADI) में 120 ट्रैक मशीनों के पीओएच से संबंधित मरम्मत कार्य हेतु 03 वर्ष की अवधि का कार्य; **निविदा संख्या: CWMCPOHADI2026-27-3; विज्ञापित निविदा मूल्य:** ₹1,35,86,57,615.03/-; **धरोहर राशि (EMD):** ₹2,71,73,200.00/-; **निविदा बंद होने की संशोधित तिथि एवं समय:** 21/08/2026 को 15:00 बजे; **निविदा खोलने की संशोधित तिथि एवं समय:** 21/08/2026 को 15:15 बजे; **IREPS वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने की तिथि: https://www.ireps.gov.in 09/06/2026; द्वितीय शुद्धिपत्र जारी करने की तिथि: 06/07/2026** ADI – 094

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

सौराष्ट्र में भारी वर्षा की स्थिति के बीच राज्य सरकार अलर्ट

प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने अमरेली, राजकोट तथा भावनगर जिलों के प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की

मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया तथा भावनगर जिला प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया की प्रेरक उपस्थिति

गांधीनगर, 07 जुलाई : सौराष्ट्र अंचल में हो रही मूशलाधार वर्षा तथा वर्तमान स्थिति को ध्यान में लेते हुए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अमरेली तथा राजकोट जिलों के प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने मंगलवार सुबह गांधीनगर से अमरेली, राजकोट तथा भावनगर जिलों के प्रशासन के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में श्री वाघाणी ने तीनों जिलों में वर्तमान स्थिति, प्रशासन की तैयारियों, निचले क्षेत्रों की स्थिति, आपदा प्रबंधन प्लान तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत समीक्षा की और प्रशासन को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस बैठक में मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया, भावनगर जिला प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, स्थानीय सांसद, विधायक तथा पदाधिकारी आदि सहभागी हुए। इसके अलावा तीनों जिलों के कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, महानगर पालिकाओं के आयुक्त और जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारी अपने एक्शन प्लान के साथ बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने तीनों जिला कलेक्टरों से निचले क्षेत्रों, नदी-नालों की वर्तमान स्थिति और जलाशयों में पानी की आवक आदि की लाइव रिपोर्ट प्राप्त की। विशेष रूप से बांधों की सुरक्षा तथा ओवरफ्लो स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने के लिए उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया।

उन्होंने भारी वर्षा के कारण विद्युत आपूर्ति तथा जलापूर्ति बाधित होने और सड़कें ब्लॉक होने जैसी तात्कालिक समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए पीजीवीसीएल, जलापूर्ति एवं सिंचाई विभाग तथा सड़क एवं भवन विभाग को स्टैंड-बाई रहने के आदेश दिए हैं। उन्होंने फिर एक बार जर्जर भवनों और होर्डिंग्स की जाँचकर अभी भी ऐसी कोई जोखिम वाली इकाई रह गई हो, तो उसे तत्काल हटाने को लेकर भी आगाह किया।

स्वास्थ्य विभाग से संभावित महामारी रोकने के लिए क्लोरीन टैब्लेट्स तथा ओआरएस का पर्याप्त भंडार रखने और तहसील स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम कार्यरत करने को कहा गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा वहाँ भोजन-पानी

की उचित व्यवस्था करने का जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया है।

श्री वाघाणी ने जोड़ा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। प्रशासन के सभी विभाग आपसी समन्वय बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं। जीरो कैजुअल्टी के दृष्टिकोण के साथ प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह सज्ज है और जनता से भी प्रशासन की सूचनाओं का पालन करने का अनुरोध किया।

अमरेली

▸▸ अमरेली जिले में इस वर्ष औसत लगभग 12 इंच बारिश हुई है, जो कुल औसत की 42 प्रतिशत से भी अधिक है। इसमें भी पिछले 24 घण्टों के दौरान ही जिले में 2 इंच से अधिक वर्षा दर्ज हुई है।

▸▸ आकस्मिक स्थिति में राहत-बचाव कार्य के लिए अमरेली में हाल में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं।

▸▸ अमरेली जिले में इस वर्ष अब तक कुल 76 नागरिकों को रेस्क्यू तथा 641 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।*

▸▸ अमरेली में भारी वर्षा के कारण राज्य सरकार के अधीनस्थ कुल 25 सड़क मार्ग बंद हुए थे, जिनमें से 19 पर यातायात बहाल कर दिया गया है।

▸▸ अमरेली के धातरवडी (100 प्रतिशत भरे हुए), सूरजवाडी (100 प्रतिशत भरे हुए), खोडियार (96 प्रतिशत भरे हुए) और रायडी (95 प्रतिशत भरे हुए) बांधों में पानी की आवक होने के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि धातरवाडी-2 (89 प्रतिशत भरे हुए) बांध को अलर्ट तथा शेल-देदुमल (78 प्रतिशत भरे हुए) बांध को वॉर्निंग लेवल पर रखा गया है।

भावनगर

▸▸ भावनगर जिले में इस वर्ष औसत लगभग 8 इंच बारिश हुई, जो कुल औसत की 30 प्रतिशत से अधिक है। इसमें पिछले 24 घण्टों के दौरान ही जिले में 3 इंच से अधिक वर्षा दर्ज हुई है।

▸▸ आकस्मिक स्थिति में राहत-बचाव कार्य के लिए भावनगर में हाल में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात है।

▸▸ भारी तथा अति भारी वर्षा के दौरान रेस्क्यू या स्थानांतरित किए गए नागरिकों के रहने के लिए जिले में कुल 982 आश्रय स्थल निर्धारित किए गए हैं।

▸▸ जिले में कुल 859 आपदा मित्रों को राहत-बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है।

▸▸ महुवा तहसील के ओथा गाँव में मालण नदी में पानी के तेज बहाव में अहमदाबाद के 8 नागरिक कार के साथ बह गए थे, जिन सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया गया है।

▸▸ जिले में राज्य सरकार अधीनस्थ सभी 74 सड़क मार्ग प्रभावित नहीं हुए हैं, जबकि पंचायत अधीनस्थ 918 मार्ग में से 7 बंद हैं। इनमें से 6 मार्गों पर डाइवर्जन तथा एक मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग शुरू किया गया है।

▸▸ भावनगर के मालण (100 प्रतिशत भरे हुए), शेत्रुंजी (100 प्रतिशत भरे हुए), रोजकी (98 प्रतिशत भरे हुए) तथा रंघोळा (96 प्रतिशत भरे हुए) बांधों में पानी की आवक होने के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है।

राजकोट

▸▸ राजकोट जिले में इस वर्ष औसत 5 इंच से अधिक वर्षा हुई है, जो कुल औसत की 18 प्रतिशत से अधिक है। इसमें पिछले 24 घण्टों के दौरान जिले में एक इंच से कम बारिश दर्ज हुई है।

▸▸ आकस्मिक स्थिति में राहत-बचाव कार्य के लिए राजकोट में हाल में एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की 1-1 टीम तैनात है।

▸▸ राजकोट के वेणू-2 (76 प्रतिशत भरे हुए) तथा आजी-2 (73 प्रतिशत भरे हुए) बांधों में पानी की आवक होने के कारण वॉर्निंग पर रखा गया है।

▸▸ किसी भी आकस्मिक स्थिति में सुदृढ़ समन्वय के लिए हर तहसील में एक उप कलेक्टर स्तरीय लायजन अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

▸▸ स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजकोट जिले की प्रत्येक तहसील में रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है।

भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति की उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में की गई सर्वग्राही समीक्षा

गांधीनगर : राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक क्षेत्रों में हुई भारी से अति भारी वर्षा के चलते प्रशासनिक तंत्र को पूर्णतः सज्ज और अलर्ट रखने के उद्देश्य से मंगलवार को गांधीनगर से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्य के प्रभावित जिलों के उच्चाधिकारियों के साथ वर्षा की वर्तमान स्थिति तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

श्री संघवी ने सूरत, नवसारी, वलसाड, भावनगर, दाहोद, पंचमहल, महीसागर, मेहसाणा, सुरेन्द्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, डांग, तापी, जूनागढ और गिर सोमनाथ सहित विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों (एसपी), जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) तथा संबंधित महानगरों के महानगर पालिका आयुक्तों से सीधे संवाद कर

ग्राउंड जीरो की स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

सभी जिलों के प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24×7 कार्यरत रहने तथा कंट्रोल रूम को लगातार एक्टिव रखने के आदेश दिए गए हैं।

निचले क्षेत्रों तथा भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यकता के अनुसार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं; जहाँ जलभराव या बाढ़ की आशंका अधिक है, वहाँ से नागरिकों को समय रहते एवं रूप से आश्रय स्थानों में स्थानांतरित करने और वहाँ भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएँ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

भारी वर्षा के दौरान जनजीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे; इसके लिए सड़कों-रास्तों, विद्युत आपूर्ति तथा संचार व्यवस्था की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग करने के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर निरंतर नजर रख रही है। आपदा के समय नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। सभी जिलों के प्रशासन आपसी समन्वय के साथ त्वरित प्रतिक्रिया (स्विफ्ट रिस्पॉन्स) सुनिश्चित करें; इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं।

तीन मौसमी सिस्टम के संयुक्त असर से गुजरात में बारिश का कहर 8 जिलों में रेड अलर्ट; बंदरगाहों पर नंबर-3 चेतावनी सिग्नल

अहमदाबाद/सूरत। गुजरात में मानसून ने बेहद आक्रामक रूप धारण कर लिया है। राज्य में एक साथ तीन शक्तिशाली मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि समुद्र में खराब मौसम और तेज हवाओं की चेतावनी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर नंबर-3 चेतावनी सिग्नल फहरा दिया गया है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात के ऊपर इस समय तीन प्रमुख मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं, जिसके कारण पूरे राज्य में व्यापक वर्षा का दौर बना हुआ है। पहला, दक्षिण-पश्चिम मानसून की मुख्य ट्रफ रेखा गुजरात से होकर गुजर रही है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार नमी पहुंच रही है। दूसरा, उत्तर-पश्चिम दिशा से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) मौसम को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहा है। वहीं तीसरा और सबसे प्रभावशाली कारक अरब सागर क्षेत्र में बना सुदृढ़ निम्न दबाव का क्षेत्र (वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया) है, जिसके कारण कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की स्थिति बनी हुई है।

इन तीनों मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, भावनगर, दमन तथा दादरा एवं नगर हवेली सहित आठ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, तेज हवाएं, बिजली गिरने तथा जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।

समुद्री तटीय क्षेत्रों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रमुख बंदरगाहों पर नंबर-3 चेतावनी सिग्नल जारी कर दिया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने की संभावना के कारण मछुआरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक समुद्र में न जाएं। जो मछुआरे पहले से समुद्र में मौजूद हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द सुरक्षित तट पर लौटने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने अमरेली, गिर सोमनाथ, भरूच, नर्मदा, खेड़ा और अरवल्ली जिलों में भी अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इन जिलों के प्रशासन को संभावित बाढ़, जलभराव और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है।

इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, बोटाद, साबरकांठा, आनंद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, दाहोद और महीसागर सहित कई जिलों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय कर दिया है और सभी संबंधित विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

राजधानी अहमदाबाद में भी मौसम विभाग ने तेज हवाओं, गरज-चमक और भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। नगर निगम ने संभावित जलभराव से निपटने के लिए पंपिंग स्टेशनों, जलनिकासी व्यवस्था और आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है। निचले इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है ताकि बारिश के दौरान पानी जमा होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, दवाइयों और आवश्यक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला : 38 दोषियों की फांसी बरकरार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा जमीयत उलमा-ए-हिंद

अहमदाबाद। वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक और बहुचर्चित फैसला सुनाते हुए विशेष सत्र न्यायालय द्वारा 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखा। साथ ही 11 अन्य दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े मृत्युदंड संबंधी मामलों में से एक माना जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। वहीं, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फैसले पर निराशा जताते हुए स्पष्ट किया कि संगठन इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा।

गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ए.वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने लगभग एक वर्ष तक चली विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों की ओर से विशेष सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर अपीलों पर विचार करने के बाद निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। इस मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों, गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजी प्रमाणों का विस्तृत परीक्षण किया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय उनके लिए अप्रत्याशित और निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि संगठन अब बिना किसी विलंब के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और दोषियों की ओर से कानूनी लड़ाई जारी रखेगा। मदनी ने कहा कि देश के वरिष्ठ आपराधिक कानून विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की सेवाएं लेकर पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मामले की पैरवी की जाएगी। उनका कहना था कि उन्हें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामले की पुनः सुनवाई के दौरान आरोपियों को न्याय मिलेगा।

मौलाना मदनी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता फिलहाल फांसी की सजा पर तत्काल रोक (स्टे) प्राप्त करना है। इसके लिए अधिवक्ताओं को आवश्यक कानूनी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में अपील की प्रक्रिया इसलिए निर्धारित की गई है ताकि यदि किसी स्तर पर न्यायिक त्रुटि रह जाए तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में उसका परीक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि अतीत में भी अनेक मामलों में निचली अदालतों द्वारा सुनाई गई कठोर सजाओं को उच्च अदालतों ने बदला है।

इस मामले में कुल 49 दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। इनमें से 39 आरोपियों को जमीयत उलमा-ए-हिंद की महाराष्ट्र कानूनी सहायता समिति ने, जमीयत उलेमा अहमदाबाद के सहयोग से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई। सभी आरोपी वर्ष 2008 से विभिन्न जेलों में बंद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस ने इन्हें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया था।

दोषियों की ओर से कई वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों ने अदालत में पक्ष रखा। इनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश नागा मुत्थु, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय थिप्से, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यारामा कृष्णन, मिहिर देसाई सहित कई अनुभवी अधिवक्ता शामिल थे। विस्तृत बहस और लंबी सुनवाई के बावजूद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अपने बयान में मौलाना अरशद मदनी ने अक्षरधाम मंदिर हमले के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस मामले में भी निचली अदालत और बाद में हाईकोर्ट ने कुछ आरोपियों को मृत्युदंड तथा अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मदनी ने कहा कि इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सभी तथ्यों का पुनः परीक्षण करेगा।

मदनी ने यह भी दावा किया कि पूर्व में ऐसे कई मामलों में, जिनमें निचली अदालतों और हाईकोर्ट ने मृत्युदंड दिया था, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कानूनी सहायता प्रदान की और बाद में संबंधित आरोपियों को राहत मिली। उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले तथा अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभावी कानूनी पैरवी के कारण कई आरोपियों को बरी किया गया या उनकी सजा कम की गई। उनका कहना था कि इसी अनुभव के आधार पर संगठन को वर्तमान मामले में भी न्याय मिलने की उम्मीद है।

इधर, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आरोपियों के परिजनों और अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी। उनका कहना था कि सभी उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी विकल्पों का उपयोग किया जाएगा।

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार विस्फोटों को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दोषियों ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री एकत्र की, बम तैयार किए और शहर के विभिन्न स्थानों पर विस्फोट किए। जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी प्रतिबंधित संगठनों इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़े थे तथा वर्ष 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों का बदला लेने की साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया।

विशेष सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 में इस मामले में 38 दोषियों को मृत्युदंड और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लगभग एक वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है।

अब इस बहुचर्चित मामले की अगली कानूनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी जाएगी। दोषियों की ओर से जल्द ही विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर किए जाने की संभावना है। वहीं, पीड़ित परिवारों और अभियोजन पक्ष की निगाहें भी अब सर्वोच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई पर टिकी रहेंगी। यह मामला न केवल आतंकवाद से जुड़े गंभीर अपराधों की न्यायिक प्रक्रिया, बल्कि मृत्युदंड, साक्ष्यों के मूल्यांकन और अपीलीय न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मानसून अलर्ट के बीच गुजरात सरकार सतर्क, सौराष्ट्र के तीन जिलों में बारिश और आपदा तैयारियों की समीक्षा करेंगे कृषि मंत्री जीतू वाघानी

गांधीनगर। गुजरात में लगातार सक्रिय मानसून और कई जिलों में हो रही भारी बारिश के बीच राज्य सरकार ने सौराष्ट्र क्षेत्र की स्थिति पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। संभावित बाढ़, जलभराव और अन्य मानसूनी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघानी मंगलवार को भावनगर, राजकोट और अमरेली जिलों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में बारिश की वर्तमान स्थिति, नदियों और बांधों के जलस्तर, आपदा प्रबंधन की तैयारियों तथा राहत एवं बचाव व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुजरात के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव से सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और राज्य के अन्य कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे प्रशासन को संभावित आपदा की आशंका के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में भावनगर के प्रभारी मंत्री कौशिक वेकारिया, संबंधित क्षेत्रों के सांसद, विधायक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा भावनगर, राजकोट और अमरेली के जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने-अपने जिलों की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की विस्तृत जानकारी देंगे।

बैठक के दौरान तीनों जिलों के कलेक्टर निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति, प्रमुख नदियों और नालों के जलस्तर, बांधों में पानी की आवक तथा संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की ताजा जानकारी साझा करेंगे। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि यदि बारिश का दौर और तेज होता है तो प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य किस प्रकार संचालित किए जाएंगे और किन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन योजनाओं की भी समीक्षा करेगी। इसमें संवेदनशील गांवों की पहचान, राहत शिविरों की व्यवस्था, बचाव दलों की तैनाती, आवश्यक खाद्यान्न एवं दवाओं की उपलब्धता तथा आपातकालीन संचार व्यवस्था जैसे विषय प्रमुख रहेंगे।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्य तत्काल शुरू किए जा सकें और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध हो।

भारी बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने, पेड़ गिरने, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने तथा जलापूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याओं की आशंका को देखते हुए जिला नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभागों से यह जानकारी ली जाएगी कि विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और आपात स्थिति में इन सेवाओं को कितनी जल्दी बहाल किया जा सकेगा।

मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में गुजरात के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों के पास न जाने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विशेष रूप से निचले और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार वर्षा के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बनी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है तथा आवश्यक संसाधनों को पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। संभावित बाढ़, जलभराव और परिवहन सेवाओं पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें।

राज्य सरकार का कहना है कि मानसून के पूरे मौसम के दौरान मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर लगातार नजर रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारी बारिश के बावजूद जनजीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे।